

हरीकृष्णा लाल
बनाम
बाबू लाल मरांडी

30 अक्टूबर 2003

[आर०सी० लहोटी एवं अशोक भान जे०जे०]

ब्रूम के लीगल मैक्सिमस 10वें संस्करण का उल्लेख किया गया है।

शालिग्राम श्रीवास्तव वि. नरेश सिंह पटेल, (2003) 2 एससीसी 176, संदर्भित।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: 2002 की सिविल अपील संख्या 5841।

झारखण्ड उच्च के निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.7.2002 से ई.पी. में राँची स्थित न्यायालय।
2001 का नंबर 1.

अपीलकर्ता-व्यक्तिगत रूप से

एस.बी. प्रतिवादी की ओर से सान्याल और सुश्री एस. जननी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

आर.सी. लाहोटी, जे. : 23-रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से झारखंड विधान सभा के लिए एक सदस्य को चुनने के लिए तत्कालीन मौजूदा सदस्य की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए जनवरी-फरवरी 2001 के महीने में चुनाव हुआ था। यद्यपि चुनाव मैदान में दो से अधिक उम्मीदवार थे, निर्णय के लिए उत्पन्न विवाद की पृष्ठभूमि में, अदालत के क्षेत्र में कानूनी लड़ाई केवल अपीलकर्ता और प्रतिवादी, कई उम्मीदवारों में से दो, के बीच जारी रही है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी ने खारिज कर दिया। वह चुनाव में भाग नहीं ले सके। प्रतिवादी को 23.2.2001 को निर्वाचित घोषित किया गया था। प्रतिवादी के चुनाव को चुनौती देते हुए और उसके चुनाव को रद्द करने की मांग करते हुए एक चुनाव याचिका, राँची में झारखंड उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। इस अपील में निर्णय के लिए

उत्पन्न होने वाले मुद्दों की सराहना करने के उद्देश्य से प्रासंगिक तथ्य। यहाँ नीचे संक्षेप में बताया गया है।

भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन पत्र 25 जनवरी 2001 से 31 जनवरी 2001 तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकता हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जो कि रामगढ़ के अनुमंडल अधिकारी थे। नामांकनों की जांच 1 फरवरी 2001 को हुई। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि, यदि कोई हो, 3 फरवरी 2001 थी। अपीलार्थी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया

अपीलकर्ता को एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित निर्धारित प्रोफार्मा में कुछ जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (इसके बाद 'संक्षेप में अधिनियम') की धारा 8 के संदर्भ में अपीलकर्ता के नामांकन आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसमें यह देखा गया था कि क्या याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा के तहत आवश्यक किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के कारण चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया था। जानकारी प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा और शपथ पत्र का फॉर्म, हालांकि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को प्रदान किया गया था, नामांकन की जांच के लिए नियुक्त तिथि और समय तक दाखिल नहीं किया गया था। जहां तक मामले के इस पहलू को स्वीकार किया जाता है, *शालिग्राम श्रीवास्तव बनाम नरेश सिंह पटेल*, [2003] 2 एससीसी 176 में इस न्यायालय के हाल के फैसले से विवाद सुलझ गया है। अपीलकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बहुत निष्पक्ष रूप से कहा है कि वह इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर, अपने नामांकन पत्र की अस्वीकृति पर विवाद करते हुए, इस याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहता।

अगला विवाद, और अब निर्णय के लिए बचा एकमात्र विवाद, यह है कि क्या प्रतिवादी द्वारा दाखिल नामांकन पत्र में कोई महत्वपूर्ण दोष है। चूँकि इस मुद्दे को अपीलकर्ता द्वारा कई तरह से उजागर किया गया है, इसलिए चुनाव याचिका में दिए गए कथनों को पुनः प्रस्तुत करना और यह बताना उपयोगी होगा कि अपीलकर्ता का मामला क्या है अपीलकर्ता के अनुसार- और

"रिटर्निंग अधिकारी को निम्नलिखित आधारों पर प्रतिवादी के नामांकन पत्र को खारिज कर देना चाहिए था-

(क) यह कि प्रतिवादी का नाम 'बाबूलाल' है। उनका उपनाम मरांडी है। उन्हें हर जगह केवल 'बाबूलाल मरांडी' नाम से ही जाना, पहचाना और संबोधित किया जाता है, किसी अन्य नाम या उपनाम से नहीं।

प्रतिवादी बाबू लाल मरांडी का नाम झारखंड राज्य विधान सभा के किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में दर्ज नहीं किया गया है।

उन्होंने अपने नामांकन पत्र दाखिल करते समय या स्कूटनी के समय रिटर्निंग ऑफिसर को झारखंड विधानमंडल के किसी भी विधानसभा क्षेत्र की प्रमाणित प्रति दाखिल नहीं की है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि उनका नाम 'बाबू लाल मरांडी' है। जो उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत किया गया है। इस प्रकार, प्रतिवादी उक्त चुनाव लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर को दाखिल किए गए उनके नामांकन पत्र में आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 36(4) के तहत पर्याप्त खामी है और उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए था।"

प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान में चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए दावे का खंडन किया है और प्रस्तुत किया है-

"कि मतदाता सूची में छपा नाम बाबू लाल मरांडी की जगह बाबू मरांडी है और उनके पिता का नाम सही है, गांव सही है और 'बाबू' और 'मरांडी' के बीच में 'लाल' नहीं छपा है। इस संबंध में, प्रस्तुत किया गया है कि उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने 29.1.2001 को रिटर्निंग ऑफिसर, रामगढ़ के समक्ष एक आवेदन दायर किया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि प्रतिवादी का सही नाम बाबू लाल मरांडी पुत्र श्री छोदू मरांडी, ग्राम कोडाईबैंक, पोस्ट ऑफिस चंदौरी, थाना तिसरी, जिला गिरिडीह है। लेकिन मतदाता सूची में गलती से उनका नाम श्री छोदू मरांडी के पुत्र बाबू मरांडी के रूप में छप गया है और उनसे अपना नाम सुधारने का अनुरोध किया गया है।"

लिखित बयान में आगे कहा गया है कि प्रतिवादी को बाबू मरांडी और बाबू लाल मरांडी के नाम से भी जाना जाता है। जाहिर है कि मतदाता सूची में 'बाबू' और 'मरांडी' के बीच में 'लाल' शब्द गलती से छूट गया है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि उत्तरदाता के नाम के नीचे में उनकी पत्नी बाबू लाल मरांडी (प्रतिवादी) की पत्नी शांति मरांडी का नाम अंकित है। निरंतरता में प्रतिवादी के पुत्र संस्तान मरांडी, पुत्र बाबू लाल मरांडी (प्रतिवादी) का नाम अंकित है। उपरोक्त याचिका का समर्थन करने वाली मतदाता सूची की एक फोटोकॉपी लिखित बयान के साथ संलग्न की गई थी। प्रतिवादी ने मतदाता सूची में उपरोक्त 'त्रुटि' के सुधार की मांग करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित एक आवेदन भी दायर किया था। आवेदन, शपथ पत्र और रसीद की प्रतियां। सुधार के लिए शुल्क जमा करते हुए लिखित विवरण भी दाखिल किया गया। प्रतिवादी ने तब प्रस्तुत किया कि मतदाता सूची में ऐसी मुद्रण गलती से प्रतिवादी की पहचान प्रभावित नहीं हुई और निश्चित रूप से यह कोई आधार नहीं है, जिसके आधार पर उसका नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता था। रिटर्निंग पदाधिकारी के द्वारा विधानसभा क्षेत्र की

मतदाता सूची को संवीक्षा के दौरान देखी गई तथा संवीक्षा के समय अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र सही पाये जाने पर स्वीकार कर लिया गया। जांच के समय किसी ने या चुनाव याचिकाकर्ता ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। रिटर्निंग अधिकारी ने प्रतिवादी के नामांकन पत्र को सही ढंग से स्वीकार कर लिया।

पार्टियों की दलीलों पर, विद्वान नामित चुनाव न्यायाधीश द्वारा तय किए गए मुद्दों में से एक था: -

"क्या प्रतिवादी बाबूलाल मरांडी का असली नाम झारखंड विधानसभा के किसी भी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है और इस प्रकार, वह 23-रामगढ़ विधानसभा सी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं हैं?"

मामले को सुनवाई के लिए निश्चित किया गया था। चुनाव याचिकाकर्ता ने घोषणा कि वह कोई सबूत नहीं पेश करना चाहता है। प्रतिवादी ने भी कोई सबूत पेश नहीं करने का फैसला किया। दलीलें सुनी गईं. हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका में दिए गए कथन को सही नहीं पाया है। उच्च न्यायालय की राय में रिटर्निंग अधिकारी ने प्रतिवादी का नामांकन पत्र स्वीकार करने में कोई गलती नहीं की है। चुनाव याचिका खारिज करने का निर्देश दिया गया है.

चुनाव याचिकाकर्ता ने यह अपील अधिनियम की धारा 116ए के तहत दायर की है

हमने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित अपीलकर्ता, जिसने सभी संभावित दृष्टिकोणों से मामले पर बहस की और प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सान्याल को सुना है। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि चुनाव याचिका को खारिज करने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए एफ दृष्टिकोण में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है और परिणामस्वरूप यह अपील भी खारिज होने योग्य है।

प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान जो इस अपील में निर्णय के लिए जीवित रहने वाले एकमात्र मुद्दे को सुनिश्चित करेंगे, अधिनियम से निकाले गए हैं और यहां पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

33. नामांकन पत्र की प्रस्तुति और वैध नामांकन के लिए आवश्यकताएँ।

(1) से (3) xxx

xxx

xxx

(4) नामांकन पत्र की प्रस्तुति पर, रिटर्निंग अधिकारी खुद को संतुष्ट करेगा कि नामांकन पत्र में दर्ज उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक के नाम और मतदाता सूची संख्या वही हैं जो मतदाता सूची में दर्ज हैं: [बशर्ते कि उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक या किसी अन्य व्यक्ति के नाम के संबंध में या मतदाता सूची या नामांकन पत्र में उल्लिखित किसी भी स्थान के संबंध में कोई गलत नाम या गलत विवरण या लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण संबंधी त्रुटि नहीं है और कोई लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण संबंधी त्रुटि नहीं है। मतदाता सूची या नामांकन पत्र में ऐसे किसी भी व्यक्ति की मतदाता सूची संख्या के संबंध में मुद्रण त्रुटि, किसी भी मामले में ऐसे व्यक्ति या स्थान के संबंध में मतदाता सूची या नामांकन पत्र के पूर्ण संचालन को प्रभावित करेगी जहां संबंध में विवरण दिया गया है। व्यक्ति या स्थान का नाम ऐसा हो जो सामान्यतः समझा जा सके; और रिटर्निंग अधिकारी ऐसे किसी भी गलत नाम या गलत विवरण या लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण त्रुटि को ठीक करने की अनुमति देगा और जहां आवश्यक हो, निर्देश देगा कि मतदाता सूची या नामांकन पत्र में ऐसे किसी भी गलत नाम, गलत विवरण, लिपिक, तकनीकी या मुद्रण त्रुटि को ठीक किया जाए। नजरअंदाज कर दिया जाएगा

(5) जहां उम्मीदवार किसी भिन्न निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक है, उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली या उसके संबंधित भाग की एक प्रति या ऐसी नामावली में सम्बंधित प्रविष्टियों की एक प्रमाणित प्रति, जब तक कि इसे इसके साथ दाखिल नहीं किया गया हो नामांकन पत्र, जांच के समय रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

36. *नामांकन की संवीक्षा.* (1) धारा 30 के तहत नामांकन की जांच के लिए निर्धारित तिथि पर, उम्मीदवार, उनके चुनाव एजेंट, प्रत्येक उम्मीदवार का एक प्रस्तावक, और प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत एक अन्य व्यक्ति, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति, ऐसे समय में उपस्थित नहीं हो सकता है और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निश्चित समय, स्थान की उचित जानकारी देगा। सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच के लिए सुविधाएं जो समय के भीतर और धारा 33 में निर्धारित तरीके से प्रदत्त की गई हैं।

(2) रिटर्निंग अधिकारी तब नामांकन पत्रों की जांच करेगा और किसी पर की गई सभी आपत्तियों पर निर्णय लेगा। नामांकन और, ऐसी आपत्ति पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, ऐसी संक्षिप्त जांच, यदि कोई हो, के बाद, जैसा वह आवश्यक समझे, कर सकता है। निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किसी भी नामांकन को अस्वीकार कर सकता है।

[(ए) कि नामांकन की जांच के लिए निर्धारित तिथि पर उम्मीदवार) या तो निम्नलिखित प्रावधानों के तहत सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं है जो लागू हो सकते हैं। अर्थात्

अनुच्छेद 84, 102, 173 और 191.)]

[इस अधिनियम का भाग II और केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 4 और 14); या

(बी) धारा 33 या धारा 34 के किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने में विफलता हुई है या

(सी) नामांकन पत्र पर उम्मीदवार या प्रस्तावक के हस्ताक्षर असली नहीं हैं

XXX XXX

XXX

(4) रिटर्निंग अधिकारी किसी भी दोष के आधार पर किसी भी नामांकन पत्र को अस्वीकार नहीं करेगा जो सारवान रूप की नहीं है

(5) रिटर्निंग अधिकारी धारा 30 के खंड (बी) के तहत इस संबंध में नियुक्त तिथि पर जांच करेगा और कार्यवाही के किसी भी स्थगन की अनुमति नहीं देगा, सिवाय इसके कि जब कार्यवाही दंगे या खुली हिंसा या कारणों से बिघ्न या बाधा हुई है। उसके नियंत्रण से परे

बशर्ते कि यदि कोई आपत्ति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उठाई गई है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, तो संबंधित उम्मीदवार को अगले दिन की तुलना में बाद में, लेकिन जांच के लिए निर्धारित तिथि के बाद एक दिन का समय दिया जा सकता है, और रिटर्निंग अधिकारी को जिस दिन कार्यवाही स्थगित की गई है उस पर अपना निर्णय दर्ज करेगा

(6) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के अपने निर्णय का समर्थन करेगा और, यदि नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाता है, तो ऐसी अस्वीकृति के लिए अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण लिखित रूप में दर्ज करेगा।

[जोर दिया गया]

यह इंगित करना उचित है कि धारा 33 की उप-धारा (4) का प्रावधान मूल रूप से अधिनियमित अधिनियम में नहीं पाया जाना था; इसे 14.12.1966 से 1966 के संशोधन अधिनियम 47 द्वारा सम्मिलित किया गया था। संशोधनों का प्रस्ताव करने वाले विधेयक के खंडों पर नोट उपरोक्त प्रावधान की बात इस प्रकार करते हैं:

“.....उपधारा (4) का नया प्रावधान प्रकृति में व्यापक है और यह यू.के. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1949 की धारा 39 की उपधारा (5) की तर्ज पर है। यह सभी सम्भावित संदेहों को दूर करने के लिए किया गया है। इसे हटाने के लिए किया गया है किसी उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक या किसी अन्य व्यक्ति के नाम के संबंध में या मतदाता सूची या नामांकन पत्र में उल्लिखित किसी भी स्थान के संबंध में किसी भी गलत नाम या गलत विवरण को सही करने की रिटर्निंग अधिकारी की शक्ति के बारे में सभी संभावित संदेह” ।

(भारत का राजपत्र, असाधारण, दिनांक 29 अगस्त, 1966, भाग 2 खंड देखें)

2 पृ. 667, 699).

प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि जहां तक धारा 33 की उप-धारा (4) का संबंध है, गैर-अनुपालन का प्रभाव केवल एक अनियमितता हो सकता है, जिसके लिए जरूरी नहीं कि नामांकन की अस्वीकृति हो। पेपर. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति उसकी राय बनाने पर निर्भर करेगी कि दोष गैर-पर्याप्त चरित्र का है या पर्याप्त चरित्र का है। कार्यवाही को स्थगित किए बिना नियत तिथि पर नामांकन पत्रों की जांच करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी पर एक वैधानिक कर्तव्य डाला जाता है। यदि रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन पत्र में कोई अनियमितता या दोष मिलता है, तो वह उम्मीदवार को, जिसका नामांकन जांच के अधीन है, रिटर्निंग अधिकारी को संतुष्ट करने का अवसर प्रदान करते हुए स्वतः जांच कर सकता है कि ऐसी कोई त्रुटि या अनियमितता मौजूद नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपत्ति उठाई जा सकती है और उस स्थिति में भी संबंधित उम्मीदवार को इसका खंडन करने के लिए समय दिया जा सकता है धारा 36 एच की उपधारा (5) के परंतुक के अर्थ में रिटर्निंग अधिकारी को अपना निर्णय स्वीकृति के माध्यम से दर्ज करना होगा या नामांकन पत्र की अस्वीकृति. यदि नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाता है तो ऐसी अस्वीकृति के कारणों का एक संक्षिप्त विवरण लिखित रूप में दर्ज करना होगा।

वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा दायर नामांकन की वैधता पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि नामांकन में प्रतिवादी का नाम मतदाता सूची में प्रदर्शित नाम से सहमत नहीं है और इसलिए नामांकन वैध नहीं है। न ही उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि प्रतिवादी उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता नहीं था। प्रतिवादी की पहचान पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। लिखित बयान में दी गई दलील और लिखित बयान के साथ दायर किए गए अनुलग्नकों से ऐसा लगता है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रतिवादी से मतदाता सूची और नामांकन पत्र में दिखाई देने वाली मामूली विसंगति पर उसे संतुष्ट करने के लिए कहा, जबकि निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में प्रविष्टि

थी "बाबू मरांडी, पिता का नाम - छोदू मरांडी, लिंग-पुरुष, उम्र - 37 वर्ष, निवासी ग्राम कोदाईबैंक, थाना तिसरी, जिला गिरिडीह", नामांकन पत्र में प्रतिवादी के नाम का उल्लेख था 'बाबूलाल मरांडी' के रूप में, अन्य सभी विवरण वही रहेंगे जो मतदाता सूची में दर्ज हैं। इस प्रकार, प्रतिवादी के नाम में एकमात्र भिन्नता 'बाबू मरांडी' और 'बाबूलाल मरांडी' थी। प्रतिवादी ने एक हलफनामा दायर करके रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दलील दी कि वह 'बाबू मरांडी' और 'बाबूलाल मरांडी' दोनों के नाम से जाना जाता है, और मतदाता सूची में 'लाल' का नाम अनजाने में, गलत और किसी भी मामले में तकनीकी था। यह सर्वविदित है कि भारतीय समाज में किसी व्यक्ति के नाम में पहला नाम, दूसरा नाम और उपनाम या परिवार का नाम शामिल होता है। प्रतिवादी का पहला नाम और परिवार का नाम मिलान किया गया; दूसरे नाम का उल्लेख नामांकन पत्र में किया गया था लेकिन मतदाता सूची में इसका उल्लेख नहीं किया गया। लिखित बयान में दी गई दलील के अनुसार मतदाता सूची में दिए गए और नामांकन पत्र में दिए गए प्रतिवादी के अन्य सभी विवरण जैसे पिता का नाम, उम्र, लिंग और निवास आदि का मिलान किया गया। इस प्रकार नामांकन पत्र में कोई खामी नहीं थी। प्रतिवादी उसी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार है जहां उसे निर्वाचक के रूप में नामांकित किया गया था, उसके लिए मतदाता सूची में प्रासंगिक प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रति दाखिल करना या जांच के समय उसे प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं था।

हरचरण सिंह बनाम एस. मोहिंदर सिंह और अन्य, एआईआर (1968) एस सी 1500 में धारा 33 और 36 में निहित प्रावधानों का उद्देश्य एक अधिनियम को उनके लॉर्डशिप द्वारा इन शब्दों में कहा गया था - "चुनाव कानून के विविध प्रावधानों का प्राथमिक उद्देश्य, जो तकनीकी प्रतीत हो सकता है, चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता की रक्षा करना है और अदालतें आमतौर पर उनके संचालन को कम नहीं करेंगी।" उनके लॉर्डशिप ने आगे कहा कि "चुनाव कानून की वैधानिक आवश्यकताओं का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। एक चुनावी विवाद सामान्य कानून के लिए अज्ञात एक वैधानिक कार्यवाही है: यह कानून या इक्विटी में कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन धारा 36(4) के तहत रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र को स्वीकार करने का हकदार है, भले ही वह दोषपूर्ण हो, यदि दोष गंभीर प्रकृति का नहीं है। उसे नामांकन पत्र को तब तक अस्वीकार नहीं करने का आदेश दिया गया है जब तक कि दोष पर्याप्त प्रकृति का न हो।" हरचरण सिंह का मामला (सुप्रा) ऐसा था जहां अपीलकर्ता को एक निर्वाचक के रूप में पहचानने के लिए विवरण विधिवत प्रस्तुत किया गया था और हालांकि नामांकन पत्र में उनकी उम्र का उल्लेख किया गया था, लेकिन प्रमाणित प्रति में नहीं पाया गया था और स्वीकृति पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की ओर से नामांकन पत्र का. सी ई *विवेका नंद गिरि बनाम नवल किशोर साही*, [1984] 3 एससीसी 10 में मतदाता सूची में दर्ज और नामांकन पत्र में बताई गई उम्र में अंतर था।

रिटर्निंग अधिकारी ने व्यक्तिगत पूछताछ से खुद को संतुष्ट किया कि डी अपीलकर्ता 25 वर्ष से अधिक उम्र का है और इसलिए चुनाव में खड़े होने के लिए सक्षम है। यह माना गया कि भले

ही प्रस्तुत की गई प्रतिलिपि चुनावी रजिस्टर में दर्ज मकान नंबर की अनुपस्थिति के कारण दोषपूर्ण थी, फिर भी दोष पर्याप्त चरित्र का नहीं था और इसलिए नामांकन पत्र को अस्वीकार न करना रिटर्निंग अधिकारी के लिए उचित था। यह माना गया कि नामांकन पत्र गलत विवरण की श्रेणी में आएगा और रिटर्निंग अधिकारी नामांकन को खारिज नहीं कर सकते। *करनैल सिंह बनाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल, हिसार एवं अन्य*, 10 ईएलआर 189 में नामांकन पत्र में सब-डिवीजन का नाम नहीं बताया गया था। हालाँकि, यह बिल्कुल स्पष्ट था कि उम्मीदवार की पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यह दोष तकनीकी माना गया था न कि पर्याप्त प्रकृति का।

उपयोगी रूप से कहावत "फाल्सा डिमॉन्स्ट्रेटियो नोसेट कम डे कोरोरे कॉन्स्टैट" का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि केवल गलत विवरण खराब नहीं होता है, अगर वस्तु के बारे में पर्याप्त निश्चितता हो। 'फाल्सा प्रदर्शन' का अर्थ है किसी लिखित उपकरण में किसी व्यक्ति या वस्तु का गलत विवरण; और इसके संबंध में उपरोक्त नियम यह दर्शाता है कि जहां विवरण एक से अधिक भागों से बना है, और एक भाग सत्य है, लेकिन एच अन्य गलत है, वहां, यदि जो भाग सत्य है वह विषय का वर्णन करता है। पर्याप्त कानूनी निश्चितता, असत्य भाग को खारिज कर दिया जाएगा और युक्ति को खराब नहीं करेगा: नियम के भीतर मामलों की विशेषता यह है कि विवरण, जहां तक यह गलत है, किसी भी विषय पर लागू नहीं होता है, और, जहां तक यह सत्य है, केवल एक पर ही लागू होता है। (ब्रूम लीगल मैक्सिम्स, 10वां संस्करण, पृ. 426-427 देखें)। ब्रूम (पृष्ठ 438 पर) एक उदाहरण उद्धृत करता है कि उचित नाम या विरासती के उपनाम में त्रुटि से विरासत शून्य नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि वसीयत से यह समझा जा सके कि इससे किस व्यक्ति को लाभ होने का इरादा था।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी क्रमांक 23 रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में विधिवत नामांकित मतदाता है। मतदाता सूची के साथ-साथ नामांकन पत्र में भी प्रतिवादी का सही वर्णन किया गया था। मतदाता सूची से उनके दूसरे नाम 'लाल' का गायब होना अनजाने में या आकस्मिक है और किसी भी मामले में केवल तकनीकी है। उत्तरदाता की पहचान के बारे में कोई संदेह नहीं है। जाहिर तौर पर इसीलिए रिट याचिकाकर्ता सहित किसी भी उम्मीदवार और किसी अन्य ने यह प्रस्तुत करके नामांकन पत्र की स्वीकृति पर कोई आपत्ति नहीं जताई कि प्रतिवादी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता नहीं था। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी संतुष्टि के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच की और अपने पास उपलब्ध निर्वाचन क्षेत्र की चुनावी सूची को देखकर संतुष्ट महसूस किया, कि प्रतिवादी बाबू लाल मरांडी वही व्यक्ति थे जिनका उल्लेख चुनावी सूची में बाबू मरांडी के रूप में किया गया था। उसी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक होने के नाते जहां से वह चुनाव लड़ रहे थे, उनके लिए मतदाता सूची से संबंधित प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति दाखिल करना आवश्यक नहीं था। उच्च न्यायालय के समक्ष, रिट याचिकाकर्ता ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं करने का विकल्प चुना है कि

रिटनिंग अधिकारी उस संतुष्टि पर पहुंचने में सही नहीं था जो उसने किया था या प्रतिवादी उस निर्वाचन क्षेत्र की चुनावी सूची में नामांकित नहीं था या वह था। किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन कराया। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी का चुनाव रद्द करने में कोई गलती नहीं की है।

और *दुर्गा शंकर मेहता बनाम रघुराज सिंह और अन्य*, एआईआर (1954) एससी 250 में संविधान पीठ ने माना है कि यदि योग्यता की कमी नामांकन पत्र पर दिखाई नहीं देती है, लेकिन यह एक ऐसा मामला है जो हो सकता है। केवल साक्ष्य द्वारा स्थापित, नामांकन पर कोई आपत्ति होने पर ही अधिनियम के तहत नामांकन पत्रों की जांच के चरण में जांच की आवश्यकता होती है। इसके बाद रिटनिंग ऑफिसर ऐसी जांच करने के लिए बाध्य है जो वह परिणाम पर उचित समझे। जिसे वह नामांकन स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। लेकिन जब उम्मीदवार मतदाता सूची और नामांकन पत्र को देखने पर उचित रूप से योग्य प्रतीत होता है और नामांकन पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है, तो रिटनिंग अधिकारी के पास नामांकन स्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता है।

संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून पूरी तरह से वर्तमान मामले पर लागू होता है। नामांकन पत्र के प्रथम दृष्टया प्रतिवादी को किसी भी तरह से अयोग्य नहीं ठहराया गया था। रिटनिंग अधिकारी ने प्रतिवादी की पहचान के बारे में खुद को संतुष्ट किया और, निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची, जो उसके पास देखने के लिए उपलब्ध थी, ने विवरण में केवल एक अप्रासंगिक तकनीकी भिन्नता की ओर इशारा किया, जैसा कि यहां पहले ही बताया गया है। यदि अपीलकर्ता का तर्क यह है कि प्रतिवादी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं था और इसलिए संबंधित मतदाता सूची की प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रति दाखिल करने में विफलता के कारण उसका नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता था, तो अपीलकर्ता को यह मामला उठाना था। वह आपत्ति ताकि रिटनिंग अधिकारी को नोटिस दिया जा सके, जो अपनी बारी में प्रतिवादी को आपत्ति को पूरा करने का अवसर दे सकता था। स्पष्टतः अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई याचिका में कोई दम नहीं है।

यह सच है कि रिटनिंग अधिकारी के समक्ष प्रतिवादी द्वारा दायर नामांकन पत्र की वैधता पर आपत्ति उठाने में अपीलकर्ता की विफलता मात्र चुनाव याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के समक्ष यह याचिका उठाने से नहीं रोकती या बाहर नहीं करती है कि नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। प्रतिवादी अस्वीकार किए जाने योग्य था या स्वीकार नहीं किया जा सकता था। अधिनियम की धारा 36 के तहत रिटनिंग अधिकारी को जो पूछताछ करनी होती है, वह संक्षेप में होती है, जिसे वह आवश्यक समझे तो कर सकता है। या तो स्वप्रेरणा से या आपत्ति उठाए जाने पर। चाहे ऐसी कोई जाँच हुई हो या नहीं और हुई हो तो परिणाम चाहे कुछ भी रहा हो, किसी नामांकन पत्र को अस्वीकार करने या स्वीकार करने के औचित्य पर चुनाव याचिका के

माध्यम से हमेशा सवाल उठाया जा सकता है। (एन.टी. वेलुस्वामी थेवर बनाम जी. राजा नैनार और अन्य, एआईआर (1959) एससी 422 देखें। लेकिन तथ्य यह है कि चुनाव याचिकाकर्ता को आवश्यक दलीलें पेश करनी होंगी और, यदि पता लगाया जाए, तो जी को आवश्यक साक्ष्य दे कर उसे प्रमाणित करना होगा। चुनाव याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसा करने में विफल रहा है। चुनाव याचिका खारिज होने का अपरिहार्य परिणाम सामने आया है।

अन्यथा भी हमें याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई याचिका में कोई तथ्य नहीं मिलता है।

अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि चुनाव याचिका में यह विशेष रूप से आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नहीं था और प्रतिवादी के लिए यह दिखाने के लिए सबूत पेश करना अनिवार्य था कि वह दाखिल करने की आवश्यकता के बिना उम्मीदवार बनने के लिए योग्य था। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष मतदाता सूची में प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियां, इस तरह की प्रस्तुति चुनाव कानून की बुनियादी बातों के विपरीत है। किसी विजयी उम्मीदवार की सफलता में हल्के से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो चुनाव को चुनौती देता है कि वह आवश्यक दलीलें पेश करे और ऐसे दावों को साबित करने के लिए सबूत पेश करे जिससे कानून में उपलब्ध किसी भी आधार पर चुनाव के परिणाम को अलग रखा जा सके। किसी चुनाव याचिका में यदि कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है तो चुनाव-याचिकाकर्ता ही असफल होता है। उच्च न्यायालय ने चुनाव-याचिकाकर्ता पर सबूत का बोझ डालते हुए इस मुद्दे को सही ढंग से तैयार किया। चूंकि चुनाव-याचिकाकर्ता द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया था, उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका को खारिज कर दिया।

अपील में कोई दम नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है। यद्यपि लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के इसे खारिज कर दिया गया है।

बीकेएम.

अपील खारिज

(अनुवादक)

मनोज कुमार सिंह

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

साहेबगंज ।